(b) if so, when the first session is planned to be held in the South?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VIDYACHARAN SHUKLA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उठाये गये घाटे**

1238. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना को भारी घाटे हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों में इसमें घाटे का प्रतिशत क्या रहा है और निरंतर हो रहे इन घाटों के लिए वास्तव में कौन व्यक्ति जिम्मेदार है;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने आम जनता को मिलने वाले दूध की कीमतों को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सरकार को प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है और क्या घाटों को पूरा करने के लिए दूध की कीमतों में वृद्धि ही एक मात्र उपाय है; और

(ङ) यदि हां, तो भविष्य के लिए सरकार का क्या आश्वासन है और यदि नहीं, तो इस पर सरकार का अंतिम निर्णय क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अयूब खान):** (क) तथा (ख) दिल्ली दुग्ध योजना का प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को उचित मूल्य पर दूध की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करना है इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली दुग्ध योजना के दूध का विक्रय मूल्य अक्सर उत्पादन लागत से कम स्तर पर रखा जाता है। जिसके लिए बजटीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना को हुए घाटे का ब्यौरा इस प्रकार है:—

| वर्ष | घाटा अंकों में / प्रतिशतता |
|---|---|
| 1992-93 | 33.18 करोड़ रुपए / 25 प्रतिशत |
| 1993-94 | 12.79 करोड़ रुपए / 11 प्रतिशत |
| 1994-95 | 8.91 करोड़ रुपए / 9 प्रतिशत |

तथापि, दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य प्रणाली में हुए सुधार के परिणामस्वरूप, घाटे के रूख में कमी आई है।

(ग) से (ङ) दूध के उत्पादन / अधिप्राप्ति / प्रसंस्करण लागत में वृद्धि के अनुरूप दिल्ली दुग्ध योजना के दूध के विक्रय मूल्य में वृद्धि करने का एक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है। सरकार ने इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

दूध के विक्रय मूल्य को उत्पादन लागत के बराबर रखकर इस घाटे को समाप्त किया जा सकता है। हाल ही में किए गए कुछ सुधारों के परिणामस्वरूप इस संयंत्र के प्रचालन की दक्षता में वृद्धि हुई है।

**Contingency Plans for Disaster Management**

1239. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that each State Government and Union Territory Administration prepares its own contingency plans for disaster management created by natural calamities like drought, flood etc.;

(b) if so, the role played by the Central Government in preparation of such plans and in funding them;

(c) whether Government have funded contingency plans for disaster management prepared by Government of Maharashtra during the last three years;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether any special relief has been provided to drought affected farmers of the state during the current financial year; and

(f) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) Government of India have prepared and circulated a Contingency Action Plan (CAP) to all State Governments/Union Territories Administrations to facilitate launching of relief operations in the wake of natural calamites. The CAP provides